



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2023/201

दर्ज तिथि:-03.07.2023

1. लाखाराम पुत्र भलाराम
2. केसरीमल पुत्र भलाराम
3. कालूराम पुत्र भलाराम
4. गुलाबाराम पुत्र भलाराम
5. वीराराम पुत्र भलाराम

जाति विश्नोई निवासी गोदारों की ढाणी गांधव कला तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. प्रहलाद चौधरी पुत्र मोडाराम चौधरी
2. भीखाराम चौधरी पुत्र मोडाराम चौधरी
जाति कलबी निवासी नई डाबली तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।
3. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता

प्रार्थी:- श्री रामजीवण विश्नोई

अप्रार्थी:- श्री चिमनसिंह चौधरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-212

राजस्थान काश्तकारी अधि0-1955

:-निर्णय:-

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र बाबत इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 74/0.3966 है0, 198/74/0.9926 है0 मौजा गोदारों की ढाणी तहसील गुडामालानी में अवस्थित है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर प्रार्थीगण के रहवासी ढाणीयां, पानी के टांके, मवेशियों के बाड़े आदि बनाए हुए है। साथ ही प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी के चारो तरफ बंदोबस्त के समय से माठे बनी हुई है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी की नेखमबंदी की जाकर पक्के नेखम स्थापित किए गए। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी के सेठें पर अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 166/5/1.



9263 है0 मौजा नई डाबली तहसील गुडामालानी अवस्थित है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी की माठों को तोड़कर अनाधिकृत कब्जा कर निर्माण करने पर आमदा है। यदि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी की माठों को तोड़कर अनाधिकृत कब्जा कर निर्माण करने में सफल हो जाते है तो इससे प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न होगा तथा इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अंत में प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर अप्रार्थीगण को मौके की यथास्थिति बनाये रखने तथा प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर आमदरफत में व्यवधान को रोकने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण असालतन वकालतन हाजिर न्यायालय हुए तथा प्रार्थना पत्र पर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अलग-अलग जाति समुदाय से संबंधित है। साथ ही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी अलग-अलग राजस्व गांवों में पृथक-पृथक अवस्थित है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपनी-अपनी खातेदारी आराजी पर वक्त बंदोबस्त से काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी आराजी की नेखमबंदी करवाने हेतु आवेदन किया। इससे नाराज होकर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर कब्जा करने के प्रयास किए। अप्रार्थी के नेखमबंदी के आवेदन पत्र को रूकवाने के उद्देश्य से प्रार्थीगण ने यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण काबिल-ए-खारिज है।
3. प्रकरण में उभयपक्षकारान की उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिप्रार्थी/प्रार्थी ने दौराने जिरह प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर अप्रार्थीगण को मौके की यथास्थिति बनाये रखने तथा प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर आमदरफत में व्यवधान को रोकने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अप्रार्थी ने दौराने जिरह करते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी आराजी की नेखमबंदी करवाने हेतु आवेदन किया। इससे नाराज होकर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर कब्जा करने के प्रयास किए। अप्रार्थी के नेखमबंदी के आवेदन पत्र को रूकवाने के उद्देश्य से प्रार्थीगण ने यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया।
4. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया है। प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-212 के प्रावधान पर विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। इस हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-212 के प्रावधान इस प्रकार है-

212. Provision for injunction and appointment of a receiver—

(1) If in the course of any suit or proceeding under this Act, it is proved by affidavit or otherwise —

(a) that any property to which such suit or proceeding relates is in danger of being wasted, damaged or alienated by any party thereto, or

(b) that any party to such suit or proceeding threatens or intends to remove or dispose of the said property in order to defeat the

ends of Justice, the court may grant a temporary injunction and, if necessary, appoint a receiver.

(2) Any person against whom an injunction has been granted or in respect of whose property a receiver has been appointed under subsection (1) may offer cash security in such amount as the court may determine to compensate the opposite party in case the suit or proceedings is decided against such persons, and on depositing the amount of such security, the court may withdraw the injunction or the order appointing a receiver, as the case may be.

5. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-212 के साथ साथ सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-39 नियम-01 व 02 में अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में प्रावधान बनाये गये हैं। जिनका उद्धरण इस प्रकार है:-

ORDER XXXIX

TEMPORARY INJUNCTIONS AND INTERLOCUTORY ORDERS

Temporary injunctions

1. Cases in which temporary injunction may be granted.—

Where in any suit it is proved by affidavit or otherwise—

(a) that any property in dispute in a suit is in danger of being wasted, damaged or alienated by any party to the suit, or wrongfully sold in execution of a decree, or

(b) that the defendant threatens, or intends, to remove or dispose of his property with a view to [defrauding] his creditors,

(c) that the defendant threatens to dispossess, the plaintiff or otherwise cause injury to the plaintiff in relation to any property in dispute in the suit, the Court may by order grant a temporary injunction to restrain such act, or make such other order for the purpose of staying and preventing the wasting, damaging, alienation, sale, removal or disposition of the property [or dispossession of the plaintiff, or otherwise causing injury to the plaintiff in relation to any property in dispute in the suit] as the Court thinks fit, until the disposal of the suit or until further orders.

2. Injunction to restrain repetition or continuance of breach.—

(1) In any suit for restraining the defendant from committing a breach of contract or other injury of any kind, whether compensation is claimed in the suit or not, the plaintiff may, at any time after the commencement of the suit, and either before or after judgment, apply to the Court for a temporary injunction to restrain the defendant from committing the breach of contract or injury complained, of, or any breach of contract or injury of a like kind arising out of the same contract or relating to the same property or right.

(2) The Court may by order grant such injunction, on such terms as to the duration of the injunction, keeping an account, giving security, or otherwise, as the Court thinks fit.

6. साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-212 के साथ साथ सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-39 नियम-04 में अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में प्रावधान बनाये गये हैं। जिनका उद्धरण इस प्रकार है:-

4. Order for injunction may be discharged, varied or set aside.—Any order for an injunction may be discharged, or varied, or set aside by the Court, on application made thereto by any party dissatisfied with such order:

Provided that if in an application for temporary injunction or in any affidavit supporting such application, a party has knowingly made a false or misleading statement in relation to a material particular and the injunction was granted without giving notice to the opposite party, the Court shall vacate the injunction unless, for reasons to be recorded, it considers that it is not necessary so to do in the interests of justice:

Provided further that where an order for injunction has been passed after giving to a party an opportunity of being heard, the order shall not be discharged, varied or set aside on the application of that party except where such discharge, variation or setting aside has been necessitated by a change in the circumstances, or unless the Court is satisfied that the order has caused undue hardship to that party.

7. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-212 के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु निम्न महत्वपूर्ण बिन्दु हैं। उक्त तीनों बिन्दुओं/सिद्धांतों पर प्रकरण का विश्लेषण निम्न प्रकार है:-

स्वामित्व एवं कब्जा	प्रार्थी	प्रार्थीगण का अभिकथन है कि प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी के सेटें पर अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी अवस्थित है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी की माठों को तोड़कर अनाधिकृत कब्जा कर निर्माण करने पर आमदा है। यदि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी की माठों को तोड़कर अनाधिकृत कब्जा कर निर्माण करने में सफल हो जाते हैं तो इससे प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न होगा तथा इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अंत में उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण को राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।
	अप्रार्थी	अप्रार्थीगण का अभिकथन है कि अप्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी आराजी की नेखमबंदी करवाने हेतु आवेदन किया। इससे नाराज होकर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर कब्जा करने के प्रयास किए। अप्रार्थी के नेखमबंदी के आवेदन पत्र को रूकवाने के उद्देश्य से प्रार्थीगण ने यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।
	निष्कर्ष	वर्तमान में उक्त आराजी को लेकर प्रार्थी का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण में प्रार्थी केवल अपनी खातेदारी आराजी पर प्रार्थीगण की आमदरफत में अप्रार्थीगण

		द्वारा उत्पन्न किये जा रहे एवं उत्पन्न किये जाने वाले व्यवधान को रोकने हेतु ताफैसल प्रार्थी का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबंद करवाना चाहते हैं। प्रकरण में खातेदारी आराजी का स्वामित्व प्रार्थीगण के पक्ष में निर्विवादित है। इस कारण खातेदारी आराजी का स्वामित्व प्रार्थीगण के पक्ष में निर्विवादित होने के आधार पर आराजी पर कब्जा भी प्रार्थीगण का होना स्पष्ट है।
सुविधा का संतुलन		प्रकरण में खातेदारी आराजी का स्वामित्व प्रार्थीगण के पक्ष में निर्विवादित है। इस कारण खातेदारी आराजी का स्वामित्व प्रार्थीगण के पक्ष में निर्विवादित होने के आधार पर आराजी पर कब्जा भी प्रार्थीगण का होना स्पष्ट है। इस प्रकार अगर प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर अप्रार्थीगण को आमदरफत में व्यवधान करने से रोकने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे अप्रार्थीगण को कोई असुविधा नहीं होती है। परंतु अगर प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर अप्रार्थीगण को आमदरफत में व्यवधान करने से रोकने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है तो इससे प्रार्थीगण को स्पष्ट रूप से असुविधा होती है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में स्पष्ट झुकाव रखता है।
अपूरणीय क्षति	प्रार्थी	प्रार्थीगण का अभिकथन है कि प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी के सेटें पर अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी अवस्थित है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी की माटों को तोड़कर अनाधिकृत कब्जा कर निर्माण करने पर आमदा है। यदि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी की माटों को तोड़कर अनाधिकृत कब्जा कर निर्माण करने में सफल हो जाते हैं तो इससे प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न होगा तथा इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी।
	अप्रार्थी	अप्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी आराजी की नेखमबंदी करवाने हेतु आवेदन किया। इससे नाराज होकर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर कब्जा करने के प्रयास किए। अप्रार्थी के नेखमबंदी के आवेदन पत्र को रूकवाने के उद्देश्य से प्रार्थीगण ने यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।
	निष्कर्ष	इस प्रकार अगर प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर अप्रार्थीगण को आमदरफत में व्यवधान करने से रोकने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे अप्रार्थीगण को कोई क्षति नहीं होती है। परंतु अगर प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर अप्रार्थीगण को आमदरफत में व्यवधान करने से रोकने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है तो इससे प्रार्थीगण को स्पष्ट रूप से अपूरणीय क्षति कारित होना स्पष्ट है।

7. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में खातेदारी आराजी का स्वामित्व प्रार्थीगण के पक्ष में निर्विवादित है। इस कारण खातेदारी आराजी का स्वामित्व प्रार्थीगण के पक्ष में निर्विवादित होने के आधार पर आराजी पर कब्जा भी प्रार्थीगण का होना स्पष्ट है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर अप्रार्थीगण को आमदरफत में व्यवधान करने से रोकने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है तो इससे प्रार्थीगण को स्पष्ट रूप से असुविधा होती है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में स्पष्ट झुकाव रखता है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर अप्रार्थीगण को आमदरफत में व्यवधान करने से रोकने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है तो इससे प्रार्थीगण को स्पष्ट रूप से अपूरणीय क्षति कारित होना स्पष्ट है। प्रकरण में स्पष्ट है कि प्रार्थी व अप्रार्थी अपनी-अपनी खातेदारी आराजी पर पृथक-पृथक रूप से स्वामित्व रखते हुए काबिज काश्त है। इसी आधार पर प्रार्थी व अप्रार्थी अपनी-अपनी खातेदारी आराजी पर पृथक-पृथक रूप से नेखमबंदी करवाने हेतु स्वतंत्र है। इसी प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थी अपनी-अपनी खातेदारी आराजी पर पृथक-पृथक रूप से आमदरफत करने हेतु स्वतंत्र है। प्रार्थी व अप्रार्थी अपनी-अपनी खातेदारी आराजी पर पृथक-पृथक रूप से नेखमबंदी/सीमाज्ञान करवाने के पश्चात आपसी कब्जे की स्थिति उत्पन्न होने पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। इस प्रकार न्यायालय प्रथमदृष्टया प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर ताफैसल दावा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित समझता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा आराजी खसरा संख्या 74/0.3966 है0, 198/74/0.9926 है0 मौजा गोदारों की ढाणी तहसील गुडामालानी पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए किसी प्रकार का हस्तक्षेप, परिवर्तन, बाधा उत्पन्न नहीं करने तथा आराजी पर काश्त नहीं करने बाबत अप्रार्थीगण को ताफैसल दावा पाबंद करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

आज 10.03.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर

गुडामालानी-बाड़मेर

सत्यमेव जयते